भारत विस्तार तकनीकी प्रणाली किसानों की खुशहाली बढ़ायेगी- भजनलाल

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह व मुख्यमंत्री ने जयपुर में ''भारत विस्तार'' का शुभारंभ किया

जयपुर, 17 फरवरी। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ''भारत विस्तार'' के माध्यम से कृषि में डिजिटल क्रांति का शंखनाद हुआ है। इस प्लेटफॉर्म से अन्नदाता किसानों को एआई आधारित

- **केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कृषि में तकनीक की उपयोगिता से राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है।**

प्रणाली में सही समय पर उनकी खेती से जुड़ी विविध जानकारियां त्वरित मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि गुलाबी नगरी जयपुर से पूरे देशभर में शुरू हुए इस

केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित ''भारत विस्तार'' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

एआई आधारित नवाचार से किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान की जाएंगी। चौहान मंगलवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित भारत विस्तार के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया है तथा भविष्य में यह 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू होगा।

चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए-नए प्रयोग किए जा रहे है। साथ ही, कृषि में तकनीक की उपयोगिता से राज्य देश को दिशा भी दिखा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ए.आई. के माध्यम से लागू होने वाली प्रणाली भारत विस्तार कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह किसानों की खुशहाली को और बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और सेवाएं सीधे बातचीत के माध्यम से तुरंत उनकी भाषा में मिलेंगी।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार उन्नत एवं तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने 'एआई हैकथॉन' तथा 'एग्री कोष' तथा ''एआई फॉर एग्रीकल्चर'' रोडमैप को भी लॉन्च किया।

जाते-जाते ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आलोचक रहे हैं। खास बात यह है कि मेजर अहमद ने हाल ही में कहा है कि ''भारत बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता।'' वहीं, नूरुल हक नूर और जोनायेद साकी जैसे नेता, जो 2024 के आंदोलन के दौरान मशहूर हुये थे, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। ये नेता अक्सर ''इंडिया आउट'' अभियान चलाते रहे हैं और बांग्लादेश की आंतरिक नीतियों में भारत के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि बांग्लादेश अब ज्यादा दृढ़ और राष्ट्रवादी रुख अपना रहा है। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि पिछली सरकार के समय का भारत-बांग्लादेश संबंधों का ''स्वर्णिम दौर'' अब समाप्त हो गया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस पहले भी कई बार भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को शामिल करते हुए एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह की बात कर चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश को इस नए आर्थिक समूह का मुख्य प्रवेश द्वार बताया है, तथा यह देश स्थल से घिरे पड़ोसी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में काम करेगा। अपने विदाई भाषण में यूनुस ने फिर कहा, ''हमारा खुला समुद्र केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का खुला दरवाजा है। यह क्षेत्र, नेपाल, भूटान और सैवन सिस्टर्स (भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य) के साथ मिलकर बहुत बड़ी आर्थिक क्षमता एवं सम्भावना रखता है।''

राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधिपति ने जोधपुर के आठ न्यायिक अधिकारियों को एपीओ किया

- **अचानक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए या कार्य के प्रति उदासीन व लापरवाही बरत रहे न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही।**
- **एपीओ किये गए अधिकारियों में जोधपुर महानगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें हाई कोर्ट में हाजिरी लगाने के आदेश दिये गये हैं।**

जोधपुर/जालोर,17 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक कार्रवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने मंगलवार को अचानक निरीक्षण करने के बाद, जिला न्यायाधीश और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के आठ न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने आदेश जारी कर बताया कि मंगलवार को हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति ने जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय का अचानक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने पर अजय शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर को एपीओ करके में हाईकोर्ट में हाजिरी लगाने के आदेश दिये। वहीं, मनीषा चौधरी विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय जोधपुर, मनीषा शर्मा एडीजे नम्बर द्वितीय जोधपुर महानगर, नेहा शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर, करुणा शर्मा सीनियर सिविल जज एवं सीजेएम जोधपुर, प्रवीण चौधरी अतिरिक्त सीनियर सिविल जज कम एसीजेएम नं. द्वितीय जोधपुर, सीमा संधु अतिरिक्त सीनियर सिविल जज कम एसीजेएम नं. 9 व मनोज जींगर अतिरिक्त सीनियर सिविल जज कम एसीजेएम नं. 7 को एपीओ करके मुख्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए। आदेश जारी होने के बाद न्यायिक हल्कों में हलचल तेज हो गई है और इसे जोधपुर की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। आदेश के अनुसार, जोधपुर महानगर एवं जिला न्यायालयों में कार्यरत कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाकर मुख्यालय हाईकोर्ट या जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। प्रशासनिक तौर पर इसे नियमित प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन एक साथ इतने अधिकारियों के एपीओ होने से इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इण्डिया एआई समिट में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिणामस्वरूप, दो समानांतर कथाएँ एक साथ चल रही हैं, एक जो पुनर्विचार का सुझाव देती है, और दूसरी जो भागीदारी की पुष्टि करती है। समीक्षा की शुरुआत अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन से जुड़े आंतरिक दस्तावेजों के रिलीज़ होने से हुई। लाखों पृष्ठों में से कुछ ड्राफ्ट ईमेल्स और नोट्स शामिल हैं, जिनमें एक वर्ष 2013 का ड्राफ्ट भी हैं, जिसमें गेट्स के व्यक्तिगत जीवन को लेकर दावे किए गए हैं। ये दस्तावेज़ आपराधिक आरोपों या न्यायिक निष्कर्षों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन दस्तावेजों में उल्लिखित होना अदालत में किसी आरोप के बराबर नहीं है।

गेट्स ने पहले स्वीकार किया था कि उन्होंने 2010 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन से मुलाकात की थी, और इन मुलाकातों को उन्होंने एक गलती माना था, जो परोपकारी चर्चाओं से जुड़ी थी। उन्होंने गलत काम करने से इनकार किया, कहा कि उन्होंने एप्स्टीन के द्वीप पर कभी यात्रा नहीं की, और अधिक सनसनीखेज दावों को गलत बताया। फिर भी, यह केवल जुड़ाव, चाहे वह कितना भी अप्रत्यक्ष क्यों न हो, सार्वजनिक संवेदनाओं को फिर से उभारने का कारण बन गया। वायरल अंशों और सुर्खियों से प्रेरित आक्रोश के इस युग में विवाद तेजी से फैलते है, सूक्ष्म बातें नहीं फैलतीं। भारत के लिए, ए.आई. इम्पैक्ट समिट सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है। यह एक महत्वाकांक्षा का बयान है, जो देश को वैश्विक ए.आई. शासन में एक जिम्मेदार और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे संदर्भ में, जो दिखता है, वही मायने रखता है, गेट्स जैसे शख्स की उपस्थिति वैश्विक भागीदारी को मजबूत करती है। लेकिन ऐसी भागीदारी से जुड़ा कोई भी विवाद समिट के वास्तविक एजेंडे से ध्यान हटा सकता है।यह भ्रम आपस में जुड़ी हुई तीन चीजों की वजह से है, वेबसाइट पर बिना स्पष्टीकरण के लिस्टिंग बदल दी गई, जाने-माने स्त्रोतों से प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स, और गेट्स फाउंडेशन से प्राप्त स्पष्ट स्पष्टीकरण। इन सब चीजों को जोड़ने वाली एक प्राधिकृत और आधिकारिक घोषणा नहीं करने से अटकलों को और बढ़ावा मिला है। अब तक, ऐसी कोई औपचारिक सरकारी घोषणा नहीं है, जो यह स्पष्ट करे कि गेट्स को औपचारिक रूप से हटा दिया गया है। न ही समिट आयोजकों से कोई सार्वजनिक और विस्तृत पुष्टि मिली है, जो फाउंडेशन के दावे के अलावा उनके अंतिम भाषण कार्यक्रम को स्पष्ट करे। जो बचा है, वह एक ''कन्युनिकेशन गैप'' है, जो यह दिखाता है कि कैसे तेजी से प्रतिष्ठा, कूटनीति और डिजिटल राजनीति एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक समिट, जिसमें एल्गोरिद्म और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस पर चर्चा की जानी है, लेकिन उसमें मानव दृष्टिकोण और संस्थागत संदेश मूल कहानी बन गए हैं।

गावस्कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतीक के रूप में सम्मानित हैं, के साथ उनके पद के अनुरूप सम्मानजनक व्यवहार किया जाए''

''हम पाकिस्तान सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि इमरान खान को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए योग्य विशेषज्ञों से तत्काल, पर्याप्त और निरंतर चिकित्सा दी जाए।

गावस्कर ने कहा, ''यह जो कुछ हो रहा है, वह बहुत खराब है। हम मैदान पर सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि जब वे वर्सेस्टरशायर के लिए एक विदेशी खिलाड़ी के रूप में चयनित होने की कोशिश कर रहे थे, तब हम दोस्त भी थे।''

तीस साल ''बेगमों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन दोनों बेगमों ने व्यक्तिगत प्रभाव और काफी हद तक तानाशाही तरीके से बांग्लादेश पर शासन किया। यह दो बेगमों के दौर का अंत है और उम्मीद है कि यह बांग्लादेश की राजनीति और शासन में एक नए दौर की शुरुआत होगी।

चुनाव जीतने के तुरंत बाद अपने बयान में तारिक रहमान ने कहा था कि नई सरकार को सभी बांग्लादेशियों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ''रेनबो नेशन'' की बात कही थी। शुरुआत से ही यह साफ दिखने लगा है कि नए प्रधानमंत्री को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी देशों में सत्रह साल के निर्वासन के बाद लौटे रहमान के शुरुआती बयानों से यह लगा कि वे विकास को प्राथमिकता देते हुए एक नए बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है और कपड़ा निर्यात पर उसकी अत्यधिक निर्भरता अब उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है।नए प्रधानमंत्री अपनी विदेश नीति और भारत के साथ संबंधों को लेकर भी गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कई तरीकों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी भरे रिश्तों को और बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने पड़ोसी देशों के रिश्तों में बिगड़ती हालत को और बढ़ाने की कोशिश की थी। मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर-पूर्व के ''सेवन सिस्टर्स'' के बारे में टिप्पणी करके भारतीय चिंताओं को बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि ये क्षेत्र जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने का उनका एकमात्र रास्ता बांग्लादेश से होकर जाता है। नई सरकार के लिए ये मुद्दे अभूतपूर्व समस्याएं पैदा कर सकते हैं। देश की नई सरकार के सामने आर्थिक विकास, बढ़ती महंगाई और लोगों, खासकर युवाओं, में बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्याएं सबसे बड़ी चुनौती हैं। रहमान की नई सरकार को, इन समस्याओं को हल करने में उसकी उपलब्धियों के आधार पर आंका जाएगा, न कि भारत के खिलाफ राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिशों के आधार पर। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा उठाए गए भड़काऊ मुद्दे जारी रहे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग की सभी संभावनाएं खत्म हो सकती हैं।

मैक्रों से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ भारत की वित्तीय राजधानी मुम्बई पहुंचे थे। मैक्रों का 2017 में सत्ता संभालने के बाद यह भारत का चौथा दौरा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का यह दौरा पिछले हफ्ते दिल्ली द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद हुआ है कि वह राफेल जेट्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने का इरादा रखते हैं, साथ ही जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैक्रों के ऑफिस ने कहा, ''इस दौरे के माध्यम से, हम भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने और फ्रांस की आर्थिक और व्यापारिक साझेदारियों को विविध करने की कोशिश कर रहे हैं।''

क्या टूट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस राज्य में तब ही कुछ सीटें जीतती है, जब द्रमुक जीतती है और सत्ता में आती है। जब द्रमुक हारती है, तो कांग्रेस भी स्वाभाविक रूप से हार जाती है। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक -भाजपा गठबंधन मुश्किल में है, लेकिन फिर राहुल की टीम को यह समझना होगा कि उन्हें किस तरफ फायदा है।

SIKAR- NEAR D.T.O OFFICE, JAIPUR ROAD, JHUNJHUNU, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 7230003521, 7412059847, 7412087309 | JAIPUR – JHUNJHUNU BYPASS, NEAR PIPRALI CHORAHA, SIKAR, JAMU AUTOMOBILES: 9694097851, 9694095757, 9887048515 | CHURU: T.R SAWHNEY MOTORS PVT. LTD. OPP. HOTEL GRAND SHEKHAWATI, JAIPUR ROAD: 8882898919.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600